(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली के सम्पूर्ण क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन झुग्गी-निवासियों को राशन-कार्ड भी जारी कर दिये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राशन कार्डों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन झुग्गी-निवासियों को बिजली, पानी और सार्वजनिक शौचालय की सुविधाएं भी प्रदान कर दी गई हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कार्य विभाग के अनुसार इसके द्वारा नई दिल्ली क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी वासियों को 11152 राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

(ङ) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

..627 **(Transferred to 3rd March, 1993.)**

Number of Women Hostels in Delhi

628. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of women hostels in Delhi and what is the number of inmates in each of the hostel;

(b) whether Government have at any time examined the working of these women's hostel to know how far even the minimum facilities required are provided by the management;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what measures have been taken by Government to improve their working conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of House.

Development of slums in Bombay and Calcutta

629. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the Eighth Plan period the Central Government had sanctioned special grants for the development of slums in Bombay and Calcutta metro cities; and

(b) if so, whether a similar request from the Karnataka Government or the development of Bangalore city has met with a lukewarm and discriminatory treatment by the Centre?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. Additional Central Assistance of Rs. 20 crores each has been allocated by the Planning Commission for special problems of Bombay and Calcutta cities during the 1992-93 Annual Plan.

(b) The Chief Minister of Karnataka made a request to the Prime Minister and the Finance Minister in 1991 for a Special Assistance of Rs. 100 crores for development of Bangalore city. The request was considered by the Govt. of India. Since Urban Development is a State subject, the Planning Commission requires that all metro development projects should form part of the State Plan. The Ministry of Urban Development also has no discretionary funds at their disposal for grant of such special assistance to State Governments.

उत्तर प्रदेश में शहरी मूलभूत सेवा योजना

630. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान गरीबों के लिए "शहरी बुनियादी सेवा योजना" के अधीन उत्तर प्रदेश में विकसित किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन): (क) शहरी मूल सेवा योजना 1990 में संशोधित की गई थी तथा 1990-91 में निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवा नामक एक नई योजना चलाई गई थी। निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवा योजना के अंतर्गत 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित बाईस कस्बों को लिया गया है :

1. कानपुर	12. बरेली
2. आगरा	13. शाहजहांपुर
3. मथुरा	14. इलाहाबाद
4. मेरठ	15. फतेहपुर
5. गाजियाबाद	16. रायबरेली
6. हापुड़	17. हरदोई
7. फरुखाबाद	18. फैजाबाद
8. वाराणसी	19. गोंडा
9. बलिया	20. लखनऊ
10. गोरखपुर	21. अलीगढ़
11. मुरादाबाद	22. मिर्जापुर

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को शहरी मूल सेवा योजना/निर्धनों के लिए शहरी मूल सेवा योजना के कार्यान्वयन के लिए क्रमशः 410.00 लाख रुपए तथा 357.60 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई थी।

Supply of contaminated water in Mayur Vihar, Delhi

631. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item under caption "Mayur Vihar contaminated water supply" which appeared in the Hindustan Times dated the 25th September, 1992;

(b) if so, the reaction of Government thereto;